

लोकवित्त/ राजस्व

अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत

Principle of Maximum Social Advantage

प्रतिपादक - डाल्टन

डाल्टन के अनुसार, “यह नियम राजस्व के मूल में विद्यमान रहता है तथा राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह हैं जिसमें राजकीय आय-व्यय संबंधी कार्यों के फलस्वरूप अधिकतम लाभ होता है”।

जिस प्रकार किसी व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य अपनी संतुष्टि अथवा कल्याण को अधिकतम करना होता है। उसी प्रकार राज्य का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ अथवा कल्याण प्राप्त करना होता है।

अर्थशास्त्र के सभी विषयों एवं कक्षाओं के नोट्स, प्रश्नोत्तर, सैंपल पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र, अभ्यास प्रश्नपत्र (हिंदी या अंग्रेजी माध्यम) के PDF आपको

www.theeconomicsguru.com पर मिल जायेंगे।

इसके साथ ही सभी हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए Free **LIVE CLASS** भी उपलब्ध है, हमारे **YOUTUBE CHANNEL "THE ECONOMICS GURU"** पर। अभी **subscribe** कर लीजिये और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिये अपने दोस्तों के बीच।

किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सम्पर्क कर सकते हैं, YOUTUBE के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या वेबसाइट के Email वाले Option में जाकर **Email** करे या WhatsApp कर सकते हैं Website में लिंक दिया गया है।

धन्यवाद

नकुल ढाली

The Economics Guru

लाभार्थी बोर्ड:

CBSE, UK Board, UP Board, Bihar Board, MP Board, CG Board, Rajasthan Board, Haryana Board

साथ ही **BA; B.COM; MA** के सभी SEMESTER लिए भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।



अभी VISIT करें

www.theeconomicsguru.com

Subscribe my **YOUTUBE** channel **THE ECONOMICS GURU**



THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

Follow me:

Facebook- *Nakul Dhali*

Instagram- *@dhali_sir*

www.theeconomicsguru.com

सिद्धांत की व्याख्या

इस सिद्धांत की महत्वपूर्ण व्याख्या **डाल्टन** के द्वारा की गई है। उनके अनुसार, “राजस्व के मूल में एक बुनियादी सिद्धांत होना चाहिए। इसे हम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कह सकते हैं। राजस्व की समस्त क्रियाएं एक प्रकार से समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में क्रय शक्ति का हस्तांतरण है। इस क्रय शक्ति के हस्तांतरण का मुख्य उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना है”।

सिद्धांत की स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हुए डाल्टन ने लिखा है कि ‘राजकीय व्यय अन्य प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ता रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर ना हो जाए। यह सीमा ही राजकीय आय और व्यय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है’।

लोकायुक्त के अधिकतम सामाजिक लाभ के तीन पहलू हैं।

प्रथम- कर संबंधी नियम- न्यूनतम सामाजिक त्याग

द्वितीय- सार्वजनिक व्यय का आवंटन।

तृतीय- सार्वजनिक व्यय तथा आय की सीमा निर्धारण।

कराधान का नियम न्यूनतम सामाजिक त्याग (Principle of Taxation)

जब किसी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है तो उसकी संतुष्टि में कमी आती है क्योंकि मुद्रा प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट प्रदान करती है। जैसे जैसे मुद्रा की मात्रा घटाई जाती है, वैसे जैसे उसके लिए मुद्रा का सीमांत उपयोगिता बढ़ता चला जाता है।

कहने का अभिप्राय है कि जब लोगों पर कर लगाया जाता है तो उनकी मुद्रा के त्याग में वृद्धि होती चली जाती है।

यदि करों के रूप में एक दी हुई मुद्रा की मात्रा इकट्ठी की जाए तो कुल सामाजिक त्याग (aggregate social welfare) न्यूनतम तभी होगा जबकि करो का भार समाज में इस प्रकार विभाजन किया जाये

ताकि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला सीमांत त्याग न्यूनतम हो।

चूँकि यह त्याग का प्रश्न है, इसलिए व्यक्ति द्वारा अधिक मुद्रा का त्याग करने पर उसका सीमांत तुष्टिकरण का त्याग बढ़ता जाता है। इसलिए न्यूनतम सामाजिक त्याग तब होगा जब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सीमांत तुष्टिगुण का त्याग समान हो।

सार्वजनिक व्यय का आवंटन (Allocation of Public Expenditure)

सार्वजनिक व्यय का स्वरूप लगभग व्यक्तिगत व्यय से मिलता जुलता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय को विभिन्न मदों पर इस प्रकार वह करता है कि उनसे प्राप्त सीमांत दृष्टिकोण बराबर हो, ठीक उसी प्रकार सरकार द्वारा किये जाने वाले व्यय विविध उपयोग में इस प्रकार किये जाने चाहिए ताकि प्रत्येक पृथक उपयोग से प्राप्त होने वाला सीमांत दृष्टि गुण बराबर हो। यदि विभिन्न परियोजन पर किए गए व्यय सीमांत तुष्टिगुण बराबर नहीं है तो एक परियोजना में कम व्यय और दूसरे परियोजन में व्यय बढ़ा देने से समाज के कुल तुष्टिगुण में वृद्धि हो जाएगी।

सार्वजनिक व्यय तथा आय की सीमा का निर्धारण

प्रथम दोनों सिद्धांत में यह पता चला है कि कराधान से सरकार को करभार इस प्रकार विभाजित करना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति की मुद्रा का सीमांत त्याग बराबर हो जाए अर्थात् सामाजिक लाभ न्यूनतम हो, जबकि सार्वजनिक व्यय पक्ष में हमने देखा कि सरकार दी हुई मुद्रा की मात्रा व्यय करती है तो उसमें विभिन्न व्यक्तियों एवं मर्दों पर इस प्रकार बांटें कि सार्वजनिक सामाजिक लाभ अधिकतम हो।

प्रोफेसर डाल्टन ने सुझाव दिया है- “सरकारी अथवा सार्वजनिक व्यय प्रत्येक दिशा में ठीक उस सीमा तक किया जाए कि उससे किसी भी क्षेत्र में इस व्यय की थोड़ी सी भी वृद्धि से समाज को प्राप्त होने वाले लाभ से, कराधान अथवा सरकारी आय के अन्य किसी साधन में की जाने वाली थोड़ी सी वृद्धि से होने वाले हानि को प्रति संतुलित किया जा सके। यह नियम सरकारी व तथा सरकारी आय दोनों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है”।

उदाहरण

इकाई	कर की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न त्याग	सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न उपयोगिता
1	70	150
2	80	135
3	90	115
4	100	100
5	110	80

सामाजिक लाभ की जांच

सामाजिक लाभ की प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं मापा जा सकता, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य मापा जा सकता है। कि राज्य में सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं।

प्रो. डाल्टन ने कुछ अप्रत्यक्ष तरीके बताए हैं जिनकी सहायता से यह जाना जा सकता है कि सरकार की वित्तीय क्रिया से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं।

जो की निम्न प्रकार है-

- समाज की विदेशी आक्रमणों अथवा आंतरिक झगड़ों में सुरक्षा करने की आवश्यकता।
- धन के उत्पादन में वृद्धि।
- धन के वितरण में सुधार।

श्रीमती हिक्स के अनुसार राजकोषीय प्रक्रियाओं का उद्देश्य उत्पादन तथा उपयोगिता को अधिकतम करना होना चाहिए। इसके लिए अधिकतम उत्पादन और अधिकतम उपयोगिता दो ऐसे मापदंड हैं जिनकी सहायता से लोक वृद्धि की क्रियाओं की जांच की जा सकती है।

अधिकतम उत्पादन (Optimum Production)

श्रीमती हिक्स के अनुसार, प्रत्येक नीति का अंतिम उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है।

अतः नियमित रूप से संसाधनों के वितरण की व्यवस्था होने पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

अधिकतम उपयोगिता (Optimum Utility)

श्रीमती हिक्स इसके अनुसार उत्पादन आदर्श के बाद लोकायुक्त का दूसरा आधार उपयोगिता है।

उत्पादन आदर्श को विभिन्न व्यवस्थाओं से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए उन व्यवस्था को चुनना होता है, जिससे अधिकतम संतुष्टि की प्राप्त हो सके।

अधिकतम सामाजिक लाभ की सीमाएं

- सामाजिक त्याग तथा सामाजिक लाभ को आंकना आसान नहीं।
- सार्वजनिक व्यय के विषय में सम सीमांत दृष्टिकोण के सिद्धांत को लागू करना ठीक नहीं होता है।
- सार्वजनिक व्यय और करों की बड़ी कठिनाई होने के कारण।
- अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का स्थान कार्यात्मक वित्त ।

अर्थशास्त्र के सभी विषयों एवं कक्षाओं के नोट्स, प्रश्नोत्तर, सैंपल पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विगत वर्षों के प्रश्नपत्र, अभ्यास प्रश्नपत्र (हिंदी या अंग्रेजी माध्यम) के PDF आपको www.theeconomicsguru.com पर मिल जायेंगे।

इसके साथ ही सभी हिंदी माध्यम तथा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के लिए Free **LIVE CLASS** भी उपलब्ध है, हमारे **YOUTUBE CHANNEL "THE ECONOMICS GURU"** पर। अभी **subscribe** कर लीजिये और ज्यादा से ज्यादा **शेयर** कर दीजिये अपने दोस्तों के बीच।

किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमसे सम्पर्क कर सकते हैं, YOUTUBE के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या वेबसाइट के Email वाले Option में जाकर **Email** करे या WhatsApp कर सकते हैं Website में लिंक दिया गया है।

धन्यवाद

नकुल ढाली

The Economics Guru

लाभार्थी बोर्ड:

CBSE, UK Board, UP Board, Bihar Board, MP Board, CG Board, Rajasthan Board, Haryana Board

साथ ही **BA; B.COM; MA** के सभी SEMESTER लिए भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध है।



अभी VISIT करें

www.theeconomicsguru.com

Subscribe my YOUTUBE channel THE ECONOMICS GURU

Follow me:

Facebook- *Nakul Dhali*

Instagram- *@nakuldhali*



THE ECONOMICS GURU
EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

www.theeconomicsguru.com

राजस्व (Public Finance)

अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत

THE ECONOMICS GURU



THE ECONOMICS GURU

EDUCATION | INSPIRATION | KNOWLEDGE

www.theeconomicsguru.com